राजधानी में बनेगा यूपी स्टार्टअप इन्क्यूबेटर हब

आशीष गुप्ता

लखनऊ। बजट के दौरान राजधानी में 30 करोड़ रुपये की लागत से यू-हब (यूपी स्टार्टअप इन्क्यूबेटर हब) बनाने का एलान किया गया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छह वर्ष पहले किया वादा भी पूरा किया है। यू-हब का मुख्यालय लखनऊ में और दूसरा इन्क्यूबेटर गौतमबुद्धनगर में बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने देश के पहले स्टार्टअप मिशन निदेशालय के लिए 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है।

सरकार के एलान से प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्टर डोज मिली है। सितंबर 2019 में योगी सरकार ने कार्यक्रम में यूपी एंजेल नेटवर्क के तहत स्टार्टअप को गति देने के लिए इनक्यूबेटर प्रोग्राम को लॉन्च करने का एलान किया था। इसके तहत अब लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में यह सिस्टम विकसित किया जाएगा।

यू-हब से ऐसे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, जिनके पास अच्छा आइडिया है और वह कंपनी बनने का माद्दा रखते हैं। हालांकि, जानकारी के अभाव में बाजार से संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, विज्ञापन और ग्राहक तक आसान पहुंच की जानकारी देने के साथ उनके उद्यम को बूस्टअप किया जाएगा। विशेषज्ञों का पैनल ऐसे नवाचारों की मदद करेगा। (संवाद)

यूपी को स्टार्टअप इकोसिस्टम में मजबूती देने का सपना छह वर्ष बाद हुआ साकार

30 करोड़ रुपये आएगी लागत, बजट के दौरान की गई घोषणा

देश में तीसरे स्थान पर है यूपी

बीएसआईएस के अध्यक्ष विनायक नाथ ने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में यूपी देश में तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 60 हजार स्टार्टअप के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक और फिर 40 हजार से ज्यादा स्टार्टअप के साथ उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पर दिल्ली है।

पहली बार किसी सरकार ने की पहल

भारत स्टार्टअप एंड इनोवेशन सोसाइटी के अध्यक्ष विनायक नाथ का कहना है कि देश में पहली बार किसी सरकार ने स्टार्टअप इन्क्यूबेटर विकसित करने की बात कही है। सामान्य रूप से टेक्निकल यूनिवर्सिटी या निजी क्षेत्रों के इन्क्यूबेटर होते हैं। यूपी सरकार ने गौर किया है कि इतने बड़े प्रदेश में स्टार्टअप की असीम संभावनाएं हैं, जिससे स्टार्टअप इको सिस्टम विकसित किया जा रहा है। प्रदेश को स्टार्टअप इकोसिस्टम में देश में पहले स्थान पर लेकर जाना है।

10 करोड़ की लागत से आईटी पार्क भी मिलेंगे : आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर आगे ले जाने के लिए लखनऊ जैसे टियर-2 व टियर-3 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसार आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इन आईटी पार्क से प्रशिक्षित युवाओं को कार्पोरेट सेक्टर में रोजगार मिल सकेगा।

एआई सिटी के पास तैयार होगा डाटा सेंटर

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। राजधानी में देश के पहले एआई सिटी की स्थापना के बाद यूपी सरकार ने डाटा पार्क और डाटा सेंटर विकसित करने पर जोर दिया है। डाटा सेंटर भी लखनऊ में एआई सिटी के पास ही बनेगा।

पिछले बजट में देश की पहली एआई सिटी की स्थापना का एलान किया गया था। मुख्यमंत्री ने नए साल की शुरुआत में जनता के नाम योगी की पाती में इसे बनाने का संकल्प दोहराया था। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया था। इसके तहत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत कर शहर का निर्माण किया जाना है।

पीपीपी मॉडल पर बन रहे एआई सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च, स्टार्टअप और डाटा एनालिटिक्स जैसी यूनिटों पर काम हो रहा है। अब सरकार ने इस बजट में 225 करोड़ रुपये से यूपी एआई मिशन और इंडिया एआई मिशन के तहत 32.82 करोड़ से 49 आईटीआई को एआई लैब व डाटा लैब बनाने की बात कही है। 30 हजार करोड़ से आठ डाटा सेंटर पार्क और दो डाटा सेंटर यूनिट खोली जाएंगी।

भारत स्टार्टअप एंड इनोवेशन सोसाइटी के अध्यक्ष विनायक नाथ का कहना है कि ऐसे सेंटर सभी जिलों में खुलने चाहिए। अभी सिर्फ महंगे कॉलेजों में ही एआई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है। ऐसे सेंटर बनने से युवाओं को पहले से ही प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा जिससे उन्हें रोजगार मिलना आसान हो सकेगा।

बजट में प्रोत्साहन से यूपी एआई मिशन से बदलेगी युवाओं की तकदीर

नवाचार, एआई आधारित तकनीक में दक्ष होंगे युवा

लखनऊ। राजधानी के छह राजकीय व अनुदानित पॉलीटेक्निक में नई टेक्नोलॉजी आधारित एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना होगी। यहां पढ़ने वाले डिप्लोमा इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नवाचार, विकास, एआई आधारित तकनीक में परिपक्व होंगे। राजकीय महिला पॉलीटेक्निक के प्रधानाचार्य संजीव कुमार ने बताया कि पॉलीटेक्निक संस्थानों में परंपरागत के साथ औद्योगिक मांग के आधार पर रोजगारपरक डिप्लोम इंजीनियरिंग के कोर्स चलाए जा रहे हैं। संस्थानों में एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना से विद्यार्थियों को बेहतर प्रयोगशाला मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि बजट में लखनऊ मंडल में एक राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना की बात भी कही गई है। इसके साथ ही सभी राजकीय पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास रूम, नवीन टेक्नोलॉजी आधारित डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की व्यवस्था की गई है। राजकीय पॉलीटेक्निकों के उन्नयन और अवस्थापना सुविधाओं के विकास का भी बजट जारी किया गया है। (संवाद)